(क) क्या यह सच है कि धनाभाव के कारण अनेक रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हा, तो दिसंबर, 1998 के अंत तक कुल कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं और इनमें से कितनी परियोजनाओं का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान कुछेक अन्य नयी परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है; यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनके निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। यह सूचना 28.7.1998 को संसद में प्रस्तुत "रेल परियोजनाओं पर श्वेत पत्र" में उपलब्ध है।

Proposed Rally of KV Teachers

*76. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Kendriya Vidhalaya Teachers' Associatioin is organising a rally in New Delhi, as a part of their phased agitation to press their various demands;

(b) if so, the details of their demands;

(c) whether any bilateral negotiations at Minister's level have since been held; and

(d) if so, the results thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOHSI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Rashtriya Kendriya Vidhalaya Adhyapak Sangh, one of the recognised teachers' association have submitted a charter of 21 demands. Their demands inter-alia include grant of Trained Graduate Teacher (TGT) grade to Yoga and Music Teachers, amendment in Primary Teacher (PRT) Scales of pay (Entry, Senior and Selection Scale), additonal increment for higher qualification to all teachers, extension of retirement age from 60-62 years, bonus to all Post Graduate Teachers (PGT). The demands are considered in accordance with the relevant rules and procedures.

The eligible Yoga teachers in Kendriya Vidyalaya Sangathan have been granted TGT scales of pay at par with their counter-parts in the schools of the Govt. of NCT of Delhi. Some more demands are at various stages of consideration. The position in respect of other demands has been explained to the representatives of teachers' associations.

No request for bilateral negotiations has been received from Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh.

Manufacture of bulk drugs by Private Sector

*77. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow the private sector licence-free entry into manufacturing of five bulk drugs, so far reserved for the public sector;

(b) if so, what are the names of these five drugs; and

(c) what are the reasons for this decision?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Vitamin B1, Vitamin B2, Folic Acid, Tetracycline and Oxytetracycline.

(c) The reasons for de-reservation are:—

(i) Review of the reservation contemplated as per paragraph

22.3 of the Modifications in Drug Policy, 1986, issued in 1994.

(ii) To encourage investment in and production of these drugs in the country for having lower prices and to reduce imports.

(iii) Stopage of production of these drugs by M/s IDPL.

निगमों को दी जाने वाली खाद्यान्नों संबंधी राजसहायता

*78. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य निगमों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित रियायती दरों पर आपूर्ति किए गए गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि पर वर्षवार और मदवार कितनी-कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या गेहूं, चावल और चीनी आदि के मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षाकृत कम राजसहायता देनी पड़ेगी; और

(ग) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम आदि को अपने अनावश्यक खर्चे कम करने के लिए कहेगी या ऐसे खर्चों की समीक्षा करेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों और चीनी पर सब्सिडि के प्रति भारतीय खाद्य निगम को तथा खाद्य तेल खाते में कमी की पूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम को निम्नलिखित राशियां निर्मुक्त की गई थीं:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष (वर्षों)	गेहं और चावल	चीनी	खाद्य तेल
1995-96	4960	422	100
1996-97	5166	900	50
1997-98	7500	400	20

(ख) जी, हां।

(ग) प्रचालनों के विशाल आकार और सब्सिडि की सीमा की दृष्टि में भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों और वहन किए गए खर्च की निरंतर समीक्षा की जाती है। राज्य व्यापार निगम के लिए खाद्य तेल खाते में कमी (i) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आर०बी०डी० पामोलीन के मूल्यों (ii) सीमा शुल्क अवसंचरना और (iii) स्वयं केन्द्रीय निर्गम मूल्य जैसे घटकों के कारण भिन्न-भिन्न रहती है जिसके परिणामस्वरूप तेलों/तिलहनों की स्वदेशी उपलब्धता मूल्य और मांग प्रभावित होते हैं।

पानीपत से कैराना के लिए रेल लाइन

*79. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पानीपत (हरियाणा) से कैराना, मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) कैराना के रास्ते पानीपत और मुजफ्फरनगर के बीच एक नई रेल लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1997-98 के दौरान स्वीकृत किया गया था। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ख) पानीपत और कैराना के बीच के भाग में फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग में यह प्रगति पर है।

(ग) दिसंबर, 1999 तक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जा सकेगा।

चीनी मिलों का औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकरण

*80. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 37 चीनी मिलें पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार प्रत्येक मामले में कब-कब पंजीकरण कराया गया था; और